वर्ष-14 - अंक 96
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर
बुधवार ,15 जुलाई 2026

RNI.No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाजियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

एक्सप्रेस-वे किनारे बनेंगे औद्योगिक हब, यूपी में 57 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी 3

ईरान पर अमेरिकी हमले, सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा 4

योगी सरकार में गन्ना किसानों के आर्थिक विकास को मिली नई रफ्तार 02

वृक्ष बचाओ, बचेगा जीवन यूपी में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव, जानें क्या है पर्यावरण का संकल्प

भारतीय चिंतन-परंपरा में कहा जाता है- वृक्षो रक्षति रक्षतः. अर्थात यदि हम वृक्ष की रक्षा करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं. प्रकृति और मनुष्य के बीच इससे सार्थक संदेश शायद ही कुछ हो सकता है कि तुम वृक्ष बचाओगे तो वे तुम्हें बचाएंगे. यही शाश्वत सत्य भी है और इसी सूत्र ने सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच अटूट संबंध प्रतिपादित किया है. जंगलों ने हमे छाया दी, नदियों ने सभ्यता का विकास किया और वृक्षों की जड़ों में हमें जीवन के मूल तत्व मिले. परंतु आधुनिक विकास की दौड़ ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हम यह भूलते गए कि हमें जीवन देने वाली प्रकृति के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है. ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती बनकर खड़ा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा उदाहरण पूरे देश के समक्ष रखा है जो प्रशासनिक दक्षता की अद्भुत मिसाल के साथ ही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की अद्भुत अभिव्यक्ति भी है.

एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए

उत्तर प्रदेश ने गत 12 जुलाई को एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधों के रोपण का रिकार्ड बनाया है. यह न सिर्फ विस्मयकारी है, बल्कि इसके पीछे योगी सरकार की तैयारी, समन्वय और विराट संकल्प भी दिखाई देता है. नेतृत्व की स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ता भी सामने आती है. ऐसा होने पर ही असंभव लक्ष्यों को साकार किया जा सकता है. गहराई से देखने पर इस पूरे अभियान की आत्मा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्यावरणीय सोच दिखाई देती है. वह हमेशा से मानते रहे हैं कि विकास और पर्यावरण-संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं और उनका यही दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश की वन नीति का आधार बना जिसने प्रशासनिक क्षमता, दूरदर्शी सोच और जनसहभागिता के अद्भुत संगम से पौधरोपण की यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

सुधीर कुमार, एडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे

पौधरोपण को सीएम योगी ने महायज्ञ की संज्ञा दी है. भारतीय परंपरा में इसके भी निहितार्थ हैं. यज्ञ का अर्थ है त्याग, समर्पण और सामूहिक कल्याण के लिए किया गया संकल्पबद्ध कर्म. जब हम कोई पौधा रोपते हैं तो अपने लिए किसी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं करते, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए छाया, शुद्ध हवा और जल-संरक्षण में निवेश करते हैं.

सनातन संस्कृति में प्रकृति देवतुल्य है

हमारी सनातन संस्कृति में वृक्ष देवतुल्य हैं, नदियां मां हैं, पर्वत पूज्य हैं तो इसलिए कि हमारे मनीषियों में प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ थी. बीते नौ सालों में यूपी सरकार ने करोड़ों पौधे रोपकर इस सह अस्तित्व को संजीवनी देने के साथ ही उस सांसस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम किया है, जिसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जीवन-दर्शन का केंद्रीय तत्व था. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और घनी आबादी वाले राज्य में, जहां औद्योगीकरण और शहरीकरण की गति तीव्र है, वहां हरित आवरण को बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. परंतु यही चुनौती इस उपलब्धि को और भी उल्लेखनीय बनाती है. 2017 के बाद से अब तक प्रदेश में 280 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं. इससे राज्य के वृक्ष आवरण में लगभग तीन लाख 80 हजार एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है.

भूगोल, जलवायु और पारिस्थितिकी को नया आकार

यह एक ऐसे परिवर्तन का प्रमाण है जो शनैः-शनैः राज्य के भूगोल, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे रहा है. बंजर भूमि में हरियाली दिखना, भूजल स्तर का ऊपर आना इस बात का प्रमाण है कि जब नीति निरंतरता के साथ लागू की जाती है, तो उसका प्रभाव संचयी होकर कालांतर में विराट रूप धारण कर लेता है. वृक्ष केवल छाया या फल नहीं देते, वे मिट्टी को बांधे रखते हैं, भूजल स्तर को संतुलित करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर जलवायु को स्थिर रखने में सहायक होते हैं, और असंख्य पशु-पक्षियों तथा जीव-जंतुओं को भोजन व आश्रय प्रदान करते हैं. इस श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र भी जरूरी है. इस अभियान ने पौधरोपण को भावनात्मक आयाम दिया है. भारतीय चिंतन भूमि को मां का दर्जा देता है. वेदों में कहा गया है- माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं. यह ऐसा जीवन-दर्शन है जो मनुष्य और प्रकृति के संबंध को मां और पुत्र के अटूट रिश्ते के समकक्ष रखता है.

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने गलती की, तो गोविंद गिरि किस बात का प्रायश्चित कर रहे हैं

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो लोग सवालों में हैं. जिनकी जवाबदेही असंख्य श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए चढ़ावे पर बिल्कुल साफ-साफ बनती है. अब तक उन्हीं की तरफ से जिस तरीके की सफाई दी जा रही है, वो भी अपने आप में नए सवाल खड़े करती है. हम बात कर रहे राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि की. जैसा कि नाम से समझा जा सकता है गोविंद देव गिरि के पास ही राम मंदिर के कोष की संपूर्ण जिम्मेदारी है. लेकिन चढ़ावा चोरी पर कई तरह की नई जानकारियां सामने आने के बीच इन्हीं गोविंद देव गिरि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा वो हैरान करता है.उन्होंने कहा कि चंपत राय से असावधानी हुई. ये तो मैंने कहा है लेकिन चंपत राय ने भी ये काम हमारे दूसरे न्यासी रहे अनिल मिश्रा को सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे. उनकी तरफ से भी ये असावधानी हो गई. मैं SIT से पूछूंगा कि ये क्यों किया है? इस्तीफा क्यों दूंगा? SIT न्यायालय नहीं होता है. SIT जांच कमेटी होती है. ये न्यायालय में बोलने के विषय होते हैं. व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं. रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्त्रोत पाठ आदि मैं कर रहा हूं. जिस स्थान में ये हुआ वहां भगवान के खिलाफ ये अपराध है और इसलिए वहां के लिए दोष के, पाप के, परिमार्जन के लिए वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं जिसके लिए 70 पंडितों की व्यवस्था की है.

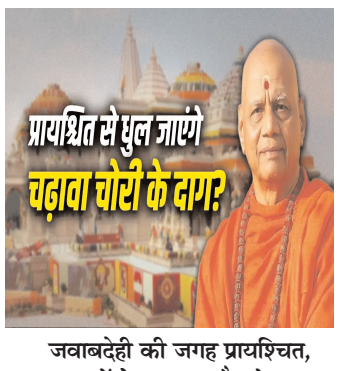

जवाबदेही की जगह प्रायश्चित, सवालों के जवाब कौन देगा

तो जवाबदेही की जगह प्रायश्चित किया जा रहा है. पूजा और अनुष्ठान से. यही वजह है कि गोविंद देव गिरि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कई सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी इन बातों से नए तरह के सवाल उठ रहे हैं. पहला सवाल है कि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पर गोविंद देव गिरि की जवाबदेही क्यों नहीं बनती? दूसरा सवाल- राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दाग पूजा पाठ-अनुष्ठान करने से क्या धुल जाएंगे? तीसरा सवाल- चंपत राय और सभी सदस्य गलती करते रहे तो खुद गोविंद गिरि क्या कर रहे थे? चौथा सवाल- ट्रस्ट के बाकी सदस्यों पर सवाल उठाकर खुद की जवाबदेही से बच जाएंगे गोविंद गिरि? पांचवां सवाल- क्या कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि को स्ढ्ढञ्ज की जांच पर ही भरोसा नहीं है?

अब जमीन घोटाले की भी हो रही चर्चा

तो सवालों का जवाब देने वाले ही खुद सवालों के घेरे में हैं. और बात सिर्फ चढ़ावा चोरी की नहीं रही. चर्चा अब जमीन घोटाले की भी होने लगी है. ट्रस्ट के ट्रस्ट पर सवालों की अगली कड़ी जमीन खरीद में धांधली के आरोपों से जुड़ती है. दो मामलों का पर्दाफाश हुआ है. दोनों अपने में हैरान करने वाले. एक खरीद में नजूल की जमीन है. तो दूसरी खरीद देवोत्तर संपत्ति की. जिसे हड़पने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने स्ढ्ढञ्ज को इस बाबत कई सबूत भी सौंपे.

नजूल की जमीन खरीदी

सबसे पहले आपको नजूल की जमीन खरीद के बारे में बताते हैं. ये अयोध्या के सुग्रीव टीला के पास की वो जगह है जिसकी खरीद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से की गई. गाटा संख्या 247 वाली ये जमीन मंदिर के निकास द्वार के नजदीक है. करीब 23 करोड़ रुपये से ज्यादा में डील तय हुई और जमीन ट्रस्ट ने खरीद ली. सवाल है, नजूल की जमीन तो सरकार की ही होती है. इसे खरीदा-बेचा नहीं जा सकता, फिर ये सौदा किस तरह किया गया.

हिंदू धर्म सेना के प्रमुख ने चंपत को घेरा

अब आपको नजूल की जमीन खरीद से जुड़े संतोष दुबे के दावों पर जानकारी देते हैं. समझते हैं, आखिर ये मामला है क्या. हिंदू धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे का कहना है कि नजूल की जमीन को ना बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है. उस जमीन को चंपत राय ने मुरलीदास से 23 करोड़ रूपये में खरीद लिया. नजूल की जमीन पर क्या हक था? आपको ये काम नहीं करना था. ये बड़ा घोटाला है.

संक्षिप्त ख़बरें

नगालैंड में असम राइफल्स पर आईईडी हमला

कोहिमा। नगालैंड के चुमौकेदिमा जिले में सोमवार को संदिग्ध आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स का एक जवान बलिदान हो गया, जबकि चार अन्य घायल हो गए। रक्षा विभाग के पीआरओ कर्नल अमित शुक्ला ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान असम राइफल्स के वाहनों को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। इससे पहले मणिपुर के उखरूल जिले में भी असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में दो जवान बलिदान हो गए थे।

बंगाल राज्यसभा उपचुनाव: भाजपा के तीनों उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के तीनों उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। भाजपा प्रत्याशी सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नामांकन पत्र जमा किए। अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार के बाद इन तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ दी थी। इसके चलते राज्यसभा की तीन सीटें खाली हुई थीं। अब भाजपा के टिकट पर वे एक बार फिर संसद के उच्च सदन में वापसी की तैयारी में हैं।

असऊपुरा में घर के बाहर बैठे अधेड़ पर हमला

ललितपुर। थाना तालबेहट क्षेत्र के ग्राम असऊपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति और उसके परिजनों पर लाठी-डंडों एवं कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गाली-गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम असऊपुरा निवासी गोविन्ददास पुत्र राधेलाल अहिरवार ने कोतवाली तालबेहट में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि 11 जुलाई 2026 की शाम करीब 7 बजे वह अपने घर के बाहर बैठे थे।

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार

नई दिल्ली(एजेंसी)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है। मामले में अन्य सह-आरोपियों पर भी अदालत ने निर्णय सुनाया है, जबकि सजा की अवधि पर जल्द सुनवाई होगी। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण कुमार की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने मार्च 2023 में सभी आरोपियों

के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और धार्मिक विद्वेष फैलाने समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव चांद बाग पुलिया के पास स्थित खजूरी खास नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर थाने में ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दंगाइयों की भीड़ को उकसाने और हिंसा की साजिश में ताहिर हुसैन की प्रमुख भूमिका थी, जिसके परिणामस्वरूप अंकित शर्मा की हत्या हुई। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब दोषियों की सजा तय करने के लिए अलग से सुनवाई होगी। इस फैसले को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

पेपर लीक पर सख्ती की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

नई दिल्ली। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि पेपर लीक मामलों की जांच और सुनवाई के लिए समय-सीमा तय करते हुए विशेष प्रक्रिया तैयार की जाए। याचिका में मांग की गई है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और काले धन से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल आरोपियों और कथित रूप से जुड़े उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

तृणमूल कांग्रेस में बढ़ा सियासी घमासान, ममता ने निर्वाचन आयोग से की त्वरित कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली(एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में संगठनात्मक विवाद गहराता जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट को अधिक समय न दिए जाने और मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की है। विवाद तब तेज हो गया जब दो जुलाई को ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने निर्वाचन आयोग से संपर्क कर स्वयं को 'असली' अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) बताया। गुट ने दावा किया कि 22 जून को हुई विशेष बैठक में संगठनात्मक बदलाव किए गए थे और आयोग से उन्हें मान्यता देने का अनुरोध किया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों से छह जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। ममता बनर्जी गुट ने तय समय सीमा के भीतर अपना

जवाब दाखिल कर दिया, जबकि बागी गुट को 10 जुलाई तक अतिरिक्त समय दिया गया। 12 जुलाई को आयोग को भेजे पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद भी उन्हें बागी गुट के जवाब की कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार दोनों पक्षों को एक-दूसरे को अपने जवाब की जानकारी देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

वारी यात्रा में ट्रक ने सात श्रद्धालुओं को रौंदा, तीन महिलाओं की मौत

पुणे(एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार सुबह वारी शोभायात्रा के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक ने पैदल चल रही वारकरी महिलाओं को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना सुबह करीब 8:30 बजे बेलसर टोल प्लाजा से जेजुरी की ओर लगभग 500 मीटर आगे हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 70 वर्षीय ट्रक चालक बुखार और सर्दी की दवा ले रहा था। दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के दौरान ट्रक अचानक बाईं ओर मुड़ गया और पैदल चल रही सात महिला श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में नंदा पवार (60), माधवी राजाराम सालगरे (55) और राजश्री शंकर भोसले (55) की मौके पर ही मौत हो गई। चार घायल महिलाओं को जेजुरी के अस्पताल के

आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी

अयोध्या(एजेंसी)। राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के बहुचर्चित मामले में जेल में बंद सभी आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सोमवार को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायालय (एंटी करप्शन कोर्ट) में पेश किया गया, जहां प्रभारी न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश

प्रतिभा नारायण ने की। इससे पहले मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने अदालत में सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच, मामले के दो प्रमुख आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव को सात दिन की पुलिस कस्टडी में देने संबंधी पुलिस की अर्जी पर मंगलवार को एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई होगी। विवेचक ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 10 जुलाई को यह आवेदन दाखिल किया था। अदालत के आगामी फैसले पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।

दुनिया का चौथा सबसे फैमिली-फ्रेंडली एयरपोर्ट बना हैदराबाद

वैश्विक रैंकिंग में भारत को बड़ी उपलब्धि, यात्रियों की सुविधाओं के दम पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हासिल किया चौथा स्थान

हैदराबाद(एजेंसी)। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे फैमिली-फ्रेंडली हवाई अड्डों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यूके की संस्था AttractionTickets.com द्वारा जारी हैपिएस्ट एयरपोर्ट्स रैंकिंग में एयरपोर्ट को 20 में से 18.5 अंक मिले हैं। मई 2026 के आंकड़ों पर आधारित इस सर्वे में दुनिया के 140 से अधिक हवाई अड्डों का मूल्यांकन किया गया। रैंकिंग के लिए यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े नौ प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया, जिनमें गूगल रिव्यू, बच्चों के लिए प्ले एरिया, फैमिली सिक्योरिटी लेन, बेबी केयर रूम, मुफ्त स्ट्रॉलर सेवा, आराम क्षेत्र, हाई-स्पीड वाई-फाई, विशाल टर्मिनल और विशेष जरूरत वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल थीं। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए प्रत्येक टर्मिनल पर आधुनिक फैमिली रूम, प्रशिक्षित सहायक स्टाफ, थेरेपी डॉग्स, योग कक्ष तथा उत्कृष्ट खान-पान और शॉपिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस उपलब्धि पर जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादिर कादिरवन ने कहा कि दुनिया के सबसे परिवार-अनुकूल हवाई अड्डों में शामिल होना संस्थान के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान यात्रियों को विश्वस्तरीय और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

रैंकिंग के लिए यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े नौ प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया, जिनमें गूगल रिव्यू, बच्चों के लिए प्ले एरिया, फैमिली सिक्योरिटी लेन, बेबी केयर रूम, मुफ्त स्ट्रॉलर सेवा, आराम क्षेत्र, हाई-स्पीड वाई-फाई, विशाल टर्मिनल और विशेष जरूरत वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल थीं।

यूपी के नए विधानभवन की तैयारी तेज

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के नए विधानभवन के निर्माण की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। गोमतीनगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नए विधानसभा परिसर के लिए सोमवार को कई कंपनियों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में अपने डिजाइन और विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इससे पहले भी कई एजेंसियां अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। प्रस्तावित परियोजना में नया विधानभवन, अत्याधुनिक सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, विधायक हॉस्टल तथा वीवीआईपी प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण शामिल है। सभी कंपनियों ने आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। योजना के अनुसार नया विधानभवन पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगा। इसे आगामी 100 वर्षों की आवश्यकताओं को

ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। परिसर में आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट प्रशासनिक सुविधाएं और डिजिटल कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अंडरग्राउंड टनल, अलग वीवीआईपी प्रवेश एवं निकास द्वार तथा विशेष ट्रैफिक प्रबंधन की भी योजना तैयार की गई है, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान गोमतीनगर में जाम की समस्या न हो। डिजाइन में आधुनिक वास्तुकला के साथ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक भी शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है।

संपादकीय

महत्वपूर्ण है पौधों को जीवित रखना

उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाकर 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान में सरकारी विभागों, पंचायतों, स्कूलों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। यह अभियान दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक जनआंदोलन का रूप ले रहा है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, हीटवेव, वायु प्रदूषण और घटता भूजल स्तर मानव जीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में वृक्ष ही प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। उत्तर प्रदेश का यह रिकॉर्ड निश्चित रूप से प्रेरणादायक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वृक्षारोपण की सफलता का वास्तविक पैमाना पौधों की संख्या नहीं, बल्कि कुछ वर्षों बाद जीवित और विकसित हुए पेड़ों की संख्या होती है। यदि लगाए गए करोड़ों पौधों में से बड़ी संख्या उचित देखभाल के अभाव में सूख जाती है, तो रिकॉर्ड केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। भारत में वर्षों से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलते रहे हैं। हर वर्ष लाखों-करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर उनकी देखभाल नहीं हो पाती। पानी की कमी, पशुओं से सुरक्षा का अभाव, उचित निगरानी न होना और स्थानीय लोगों की भागीदारी कम होने के कारण बड़ी संख्या में पौधे कुछ ही महीनों में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब आवश्यकता केवल वृक्षारोपण की नहीं, बल्कि 'वृक्ष संरक्षण' की है। एक पौधा तभी पेड़ बनता है जब उसे कम से कम तीन से पाँच वर्षों तक निरंतर देखभाल मिले। नियमित सिंचाई, समय-समय पर खाद, पौधों के चारों ओर सुरक्षा जाली, खरपतवार की सफाई और स्थानीय समुदाय की निगरानी अत्यंत आवश्यक होती है। यदि इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो पौधे लगाने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय समाज की होती है। जिस गांव, मोहल्ले या विद्यालय में पौधे लगाए जाएं, वहां के लोगों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए। यदि प्रत्येक परिवार एक या दो पौधों को गोद लेकर उनकी देखभाल का संकल्प ले, तो वृक्षों की जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को अपने लगाए पौधों की प्रगति दर्ज करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित होगी। सरकार को भी केवल वृक्षारोपण के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि पौधों की जीवित रहने की दर पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। नियमित सर्वेक्षण, डिजिटल निगरानी, भू-स्थानिक तकनीक और सामाजिक ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लगाए गए पौधे वास्तव में पेड़ों में बदल रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पौधों की मृत्यु अधिक हो, वहां पुनः वृक्षारोपण और विशेष संरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि स्थानीय जलवायु के अनुकूल और देशी प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जाए। पीपल, बरगद, नीम, शीशम, अर्जुन, जामुन, आम और अन्य स्थानीय प्रजातियां न केवल लंबे समय तक जीवित रहती हैं, बल्कि पक्षियों, पशुओं और जैव विविधता के लिए भी अधिक उपयोगी होती हैं। विदेशी प्रजातियों की तुलना में देशी वृक्ष स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक मजबूत बनाते हैं। वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। फलदार वृक्ष किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, छायादार वृक्ष शहरों में तापमान कम करने में मदद करते हैं, जबकि जंगल पर्यटन और जैव विविधता के संरक्षण का आधार बनते हैं। इसलिए वृक्षों को विकास के विरोधी नहीं, बल्कि सतत विकास के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस सोच को विकसित करने की है कि वृक्षारोपण एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि वर्षों तक चलने वाला दायित्व है। पौधे लगाना आसान है, लेकिन उन्हें पेड़ बनाना कठिन और अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि उत्तर प्रदेश अपने लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधों का बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक पेड़ों में बदलने में सफल होता है, तो यह केवल रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य पर्यावरणीय विरासत बन जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की असली जीत पौधे लगाने में नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखने में है। हर नागरिक यदि एक पौधे को पेड़ बनाने का संकल्प ले, तो करोड़ों पौधों का यह अभियान वास्तव में हरित क्रांति का आधार बन सकता है। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तभी पूर्ण सफलता कहलाएगा जब आने वाले वर्षों में यही पौधे घने वृक्षों का रूप लेकर स्वच्छ हवा, हरियाली और बेहतर भविष्य का आधार बनेंगे।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

मेष -मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रह सकता है। शुभ योगों का प्रभाव आपके कार्यों में गति ला सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है, जबकि नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

वृषभ -वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहने की संभावना है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और कारोबार में विस्तार की दिशा में उठाए गए कदम सफल साबित हो सकते हैं।

मिथुन -मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन योजनाओं को सफल बनाने वाला रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य में प्रगति के मार्ग खुल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं।

कर्क -कर्क राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का अच्छा साथ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।

सिंह -सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और आपकी प्रतिभा लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। व्यापार में नए अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है।

कन्या -कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ समाचार लेकर आ सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ने की संभावना है। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला-तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिला सकता है। लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

वृश्चिक -वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज परिश्रम का पूरा लाभ मिलने के योग हैं। आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं और निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभदायक समझौते हो सकते हैं।

धनु -धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

मकर -मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में सम्मान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकते हैं।

कुंभ-कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरपूर रह सकता है। नई योजनाओं पर किया गया प्रयास सफल हो सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

मीन-मीन राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का अच्छा सहयोग मिलने के संकेत हैं। कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं और व्यापार में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है।

योगी सरकार में गन्ना किसानों के आर्थिक विकास को मिली नई रफ्तार

ऐसे में गन्ना क्षेत्र की मजबूती सीधे किसानों की समृद्धि और प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान, चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का परिणाम आज किसानों की बढ़ती आय, समयबद्ध भुगतान और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही नई खुशहाली के रूप में सामने आ रहा है। एक समय ऐसा था जब गन्ना किसानों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। चीनी मिलों से भुगतान में देरी, बढ़ती उत्पादन लागत, सिंचाई संबंधी कठिनाइयां, बंद पड़ी चीनी मिलें और सीमित तकनीकी संसाधन किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। कई किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित होती थी।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहां लाखों किसान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गन्ना खेती और उससे जुड़े उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गन्ना केवल एक फसल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आय, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार है। ऐसे में गन्ना क्षेत्र की मजबूती सीधे किसानों की समृद्धि और प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान, चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का परिणाम आज किसानों की बढ़ती आय, समयबद्ध भुगतान और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही नई खुशहाली के रूप में सामने आ रहा है।

एक समय ऐसा था जब गन्ना किसानों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। चीनी मिलों से भुगतान में देरी, बढ़ती उत्पादन लागत, सिंचाई संबंधी कठिनाइयां, बंद पड़ी चीनी मिलें और सीमित तकनीकी संसाधन किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। कई किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित होती थी। ऐसे में गन्ना खेती किसानों के लिए लाभ का नहीं, बल्कि अनिश्चितता का विषय बनती जा रही थी। प्रदेश सरकार ने किसानों को रू0 03.22 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया है। प्रदेश सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए गन्ना क्षेत्र में व्यापक सुधारों की शुरुआत की। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, चीनी मिलों की कार्यक्षमता बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने जैसे अनेक निर्णय लिए गए। वर्तमान सरकार ने 04 नई चीनी मिलों की स्थापना 06 चीनी मिलों का पुन: संचालन और 44 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार किया है। प्रदेश में अब 120 चीनी मिलें क्रियाशील है। इन नीतिगत सुधारों ने गन्ना खेती को नई ऊर्जा प्रदान की और किसानों का विश्वास मजबूत किया। प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तेजी से किया गया तथा चीनी मिलों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समय पर भुगतान मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया। अब किसानों को खेती के लिए महंगे ब्याज पर ऋण लेने की आवश्यकता पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। वे समय पर उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर पा रहे हैं, जिससे खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई है।प्रदेश सरकार ने गन्ना खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया है। ट्रेंच विधि, ड्रिप सिंचाई, सहफसली खेती तथा उन्नत किस्मों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। गन्ना विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती की नई तकनीकों से परिचित कराया गया। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। ड्रिप सिंचाई से जल संरक्षण हो रहा है, ट्रेंच विधि से उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा खेती की लागत में कमी आई है। इससे किसानों की आय में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। गन्ना क्षेत्र में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति ने भी किसानों और चीनी उद्योग दोनों को नई दिशा दी है। पहले जहां चीनी मिलों की आय मुख्य रूप से चीनी उत्पादन पर निर्भर रहती थी, वहीं अब एथेनॉल उत्पादन ने आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराए हैं। इससे चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनी है। प्रदेश में वर्ष 2017 के पूर्व एथेनाल का उत्पादन मात्र 42 करोड़ लीटर था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2025-26 में बढ़कर 188 करोड़ लीटर हो गया है, जो देश में सर्वाधिक है। गन्ने की बढ़ती मांग ने किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों का भी विस्तार हुआ है।

प्रदेश में वर्षों से बंद पड़ी कई चीनी मिलों के पुनरुद्धार तथा नई इकाइयों की स्थापना के प्रयासों ने भी गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। अब किसानों को अपनी फसल दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता कम हुई है। परिवहन लागत में कमी आने से उनकी आय में वृद्धि हुई है। वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। इन सुधारों का प्रभाव किसानों के जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आर्थिक मजबूती मिलने से ग्रामीण परिवारों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। किसान अब अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश कर रहे हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवास और अन्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने भी पारदर्शिता और सुविधा दोनों को बढ़ावा दिया है। गन्ना पर्ची से लेकर भुगतान तक की ऑनलाइन व्यवस्था ने किसानों का समय बचाने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल और भरोसेमंद बनाया है। महिलाओं की भागीदारी से भी गन्ना आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं खेती के साथ-साथ डेयरी, पशुपालन और छोटे उद्यमों से जुड़कर परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इससे आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका भी अधिक मजबूत हुई है। गन्ना

-अमित कुमार शुक्ला

सुलतानपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संवरी ग्रामीण महिलाओं की तकदीर

जनपद के विकास खण्ड कूड़वार के ग्राम उत्तरगांव की निवासी श्रीमती ललिता मौर्य की सफलता की कहानी इस सरकारी प्रयास का एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण है। कभी अत्यधिक आर्थिक तंगी, कच्चे मकान और सीमित आय के कारण गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझने वाली ललिता मौर्य के जीवन में यह बड़ा बदलाव शासन की जनहितैषी योजनाओं के कारण ही संभव हो सका है। उनके पति पूर्व में चौकीदारी का कार्य करते थे, जिससे बड़े परिवार का दैनिक खर्च चलाना भी मुश्किल होता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजनाओं ने उन्हें एक नया जीवन मार्ग दिखाया। ललिता मौर्य ने गाँव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर 'लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह' की सदस्यता ग्रहण की, जो 'ठाकुर बाबा ग्राम संगठन' और 'जागृति महिला संकुल स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.)' के अंतर्गत सक्रियता से कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियों के अनुरूप जनपद सुलतानपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में यह अभियान ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवारों की आय में निरंतर वृद्धि करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। जनपद के विकास खण्ड कूड़वार के ग्राम उत्तरगांव की निवासी श्रीमती ललिता मौर्य की सफलता की कहानी इस सरकारी प्रयास का एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण है। कभी अत्यधिक आर्थिक तंगी, कच्चे मकान और सीमित आय के कारण गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझने वाली ललिता मौर्य के जीवन में यह बड़ा बदलाव शासन की जनहितैषी योजनाओं के कारण ही संभव हो सका है। उनके पति पूर्व में चौकीदारी का कार्य करते थे, जिससे बड़े परिवार का दैनिक खर्च चलाना भी मुश्किल होता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजनाओं ने उन्हें एक नया जीवन मार्ग दिखाया। ललिता मौर्य ने गाँव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर 'लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह' की सदस्यता ग्रहण की, जो 'ठाकुर बाबा ग्राम संगठन' और 'जागृति महिला संकुल स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.)' के अंतर्गत सक्रियता से कार्य कर रहा है। समूह से जुड़ने के उपरान्त जिला प्रशासन की देखरेख में उन्हें विधिवत प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक वित्तीय सहायता सुलभ कराई गई। प्रारम्भिक चरण में उन्होंने 'समूह सखी' के रूप में अपनी क्षमता का परिचय दिया, जिससे उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य ग्रामीण महिलाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का गहरा अनुभव प्राप्त हुआ। इस आजीविका यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर अचार, पापड़, मल्टीग्रेन आटा, बेसन, सत्तू तथा मक्का आधारित विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री का उद्यम प्रारम्भ किया। व्यवसाय के शुरुआती दौर में उत्पाद निर्माण, विपणन, ब्रांडिंग और बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी कई व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आईं, जिनका जिला एवं ब्लॉक स्तरीय तकनीकी टीमों ने त्वरित संज्ञान लिया। जिला प्रशासन द्वारा ललिता मौर्य के उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग सुनिश्चित कराई गई और उन्हें विभिन्न विकास प्रदर्शनियों, राजकीय मेलों तथा विशेष स्टॉलों में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया गया। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएमएफएमई' योजना और स्वयं सहायता समूह के वित्तीय कोष से उन्हें समय पर पूँजी उपलब्ध कराई गई। इन समन्वित प्रशासनिक प्रयासों के फलस्वरूप उनके उत्पादों की बाजार में मांग और बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान में ललिता मौर्य का यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम अत्यंत सफलता के साथ संचालित हो रहा है, जिससे वह प्रतिवर्ष लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उन्होंने अपने इस उद्यम में गाँव की पाँच अन्य निर्धन महिलाओं को भी नियमित रोजगार प्रदान कर उनके परिवारों को आर्थिक संबल दिया है। इसके अतिरिक्त, शासन की कल्याणकारी नीतियों के तहत ललिता के परिवार को पक्का आवास और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी स्वीकृत की गई हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है। जनपद सुलतानपुर में इस मिशन की सफलता का मुख्य आधार त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 10 से 20 महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है। इन समूहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा 1500 रुपये का स्टार्ट-अप फंड और तीन माह की सफल अवधि के उपरान्त 15,000 रुपये की रिवाल्विंग फंड राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाती है, ताकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। समूहों के प्रभावी नियंत्रण और क्षमता संवर्धन के लिए 06 से 15 समूहों को मिलाकर 'ग्राम संगठन' का निर्माण किया जाता है, जिसके कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार की ओर से 75,000 रुपये का वित्तीय प्रावधान है। इसी प्रकार, विकास खण्ड स्तर पर व्यापक आर्थिक परियोजनाओं के संचालन हेतु 3 से 4 क्लस्टरों को मिलाकर 'संकुल स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.)' का गठन किया जाता है, जिसके सुदृढ़ीकरण के लिए 3,50,000 रुपये का वित्तीय सहयोग सुनिश्चित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के बड़े अवसर प्रदान करने के लिए गहन विकास खण्डों में सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो क्रेडिट प्लान) के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अधिकतम 1,10,000 रुपये की सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) उपलब्ध कराई जाती है।

इसके साथ ही रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप छह माह पुराने और सफल ग्रेडिंग वाले समूहों को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट लिंकेज और प्रथम किश्त के रूप में 1 लाख रुपये का ऋण मात्र 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर स्वीकृत किया जाता है, जिसमें नियमित पुनर्भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट का लाभ भी मिलता है।

जनपद सुलतानपुर के विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्थापित यह सशक्त संस्थागत मंच ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने और वित्तीय सेवाओं तक हर गरीब की सरल पहुंच बनाने में निरंतर मील का पत्थर साबित हो रहा है। श्रीमती ललिता मौर्य जैसी कर्मठ महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास और सरकार की योजनाओं का यह सफल क्रियान्वयन जनपद की समस्त ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने तथा विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहा है।

जनपद-सुलतानपुर

स्वयं सहायता समूहों से सशक्त होंगे वरिष्ठ नागरिक

देश में जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत आवासीय जनगणना की जा रही है। दूसरे चरण में प्रत्येक परिवार तथा बेघर व्यक्तियों की जनगणना होगी। इससे पहले नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर विवरण का सत्यापन और आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश की जनसंख्या, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने में सहायक होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं और कल्याणकारी नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करती है। जनगणना से जुड़ी शुरुआती चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण चिंता देश की बदलती जनसांख्यिकीय संरचना को लेकर सामने आ रही है। भारत की कुल प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे पहुंच चुकी है, जिससे भविष्य में युवाओं की हिस्सेदारी घटने और बुजुर्ग आबादी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। महानगरों में विवाह की बढ़ती उम्र, कम संतान की प्रवृत्ति तथा बदलती जीवनशैली भी इस परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जनगणना के आंकड़े देश की भावी सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।चीन और जापान जैसे देशों ने वृद्ध होती आबादी की चुनौती का सामना किया है। वहां वरिष्ठ नागरिक अनुभव और कौशल के आधार पर आज भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत लंबे समय तक स्वयं को युवाओं का देश मानता रहा, लेकिन घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा भविष्य में बुजुर्ग आबादी के बढ़ने का संकेत दे रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को केवल आश्रित नहीं, बल्कि उत्पादक संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से देश में अनेक बुजुर्गों को पर्याप्त सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पातीं। परिवारों के विघटन और उपेक्षा की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार और समाज दोनों को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की होगी।इस दिशा में एक सकारात्मक पहल वर्ष 2004 में तमिलनाडु में सुनामी के बाद सामने आई। आर्थिक संकट के बावजूद अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने हार मानने के बजाय स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) बनाकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू किया। प्रारंभ में सरकारी स्तर पर पर्याप्त योजनाएं या प्रोत्साहन नहीं थे, फिर भी यह पहल लगातार आगे बढ़ती रही। आज यह अभियान तमिलनाडु से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच चुका है। आज हजारों वरिष्ठ नागरिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस मॉडल को विस्तार देने की आवश्यकता है, ताकि वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनें, एक-दूसरे का सहयोग करें और अपने अनुभव से समाज व अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकें। वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों ने आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन समूहों से जुड़े लगभग 70 प्रतिशत बुजुर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं। नियमित छोटी बचत के आधार पर उन्होंने करोड़ों रुपये का सामूहिक कोष तैयार किया, जिससे जरूरतमंद सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया गया और आय के नए अवसर भी विकसित हुए। बिहार के सुपौल जिले का यह मॉडल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां कई बुजुर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होकर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। इस पहल की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को भी प्रोत्साहन देना शुरू किया है। यह मॉडल आत्मनिर्भर और सम्मानजनक वृद्धावस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वास्तविक समाधान तभी संभव है, जब प्रशासन, समाज और वरिष्ठ नागरिक मिलकर कार्य करें। बढ़ती उम्र के कारण भले ही बुजुर्ग शारीरिक रूप से पहले जैसे सक्रिय न रहें, लेकिन उनका अनुभव, ज्ञान और निर्णय क्षमता समाज की अमूल्य पूंजी है। उन्हें ऐसे कार्यों में अवसर दिए जाने चाहिए, जहां मार्गदर्शन, सलाह और अनुभव की आवश्यकता हो। युवा ऊर्जा और वरिष्ठों के अनुभव का समन्वय राष्ट्र निर्माण को नई दिशा दे सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को केवल सहायता का पात्र नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की सफल पहल इसकी संभावना सिद्ध कर चुकी है। अब आवश्यकता है कि सरकार और समाज मिलकर इस मॉडल को व्यापक स्तर पर अपनाएं।

भारत लंबे समय तक स्वयं को युवाओं का देश मानता रहा, लेकिन घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा भविष्य में बुजुर्ग आबादी के बढ़ने का संकेत दे रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को केवल आश्रित नहीं, बल्कि उत्पादक संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से देश में अनेक बुजुर्गों को पर्याप्त सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पातीं। परिवारों के विघटन और उपेक्षा की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार और समाज दोनों को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की होगी।इस दिशा में एक सकारात्मक पहल वर्ष 2004 में तमिलनाडु में सुनामी के बाद सामने आई। आर्थिक संकट के बावजूद अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने हार मानने के बजाय स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) बनाकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू किया। प्रारंभ में सरकारी स्तर पर पर्याप्त योजनाएं या प्रोत्साहन नहीं थे, फिर भी यह पहल लगातार आगे बढ़ती रही। आज यह अभियान तमिलनाडु से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच चुका है।

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 न0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

एक्सप्रेस-वे किनारे बनेंगे औद्योगिक हब, यूपी में 57 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी

26 जिलों में 27 स्थानों पर विकसित हो रहे आईएमएलसी, 10,795 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेस-वे के किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) विकसित कर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे के आसपास विकसित होने वाले ये औद्योगिक केंद्र निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रदेश के 26 जिलों में 27 स्थानों पर आईएमएलसी विकसित किए जा रहे हैं। परियोजना के लिए करीब 12,700 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से

अब तक 10,795 एकड़ (85.73 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण और पुनर्ग्रहण पूरा किया जा चुका है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2025 में सभी 27 आईएमएलसी स्थलों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया गया था। इसके बाद उद्योग जगत से बेहतर प्रतिक्रिया मिली है। अब तक करीब 1,110 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 57,148 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। आईएमएलसी परियोजना के तहत उन्नाव नोड में 125.992 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है। यहां करीब 2,068 करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे लगभग 2,160 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं मेरठ नोड में 20.64 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में करीब 321.04 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 1,814 रोजगार मिलने की उम्मीद है। हरदोई नोड में 7.91 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां 142.50 करोड़ रुपये के निवेश से करीब 326 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब तक तीन जिलों में आठ कंपनियों को कुल 154.542 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 2,531 करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित हुआ है और लगभग 4,300 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि एक्सप्रेस-वे आधारित औद्योगिक विकास के जरिए प्रदेश में विनिर्माण, भंडारण और परिवहन क्षेत्र को मजबूत किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभर सके।

बिसवां में केंद्रीय प्रभारी ने परखे विकास कार्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां सीतापुर। भारत सरकार द्वारा आकांक्षात्मक विकास खंड बिसवां, जनपद सीतापुर हेतु नामित केंद्रीय प्रभारी अधिकारी उमेश कुमार सिंह (IRPS) ने सोमवार को विकास खंड बिसवां का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीक्षा जोशी (IAS) एवं खंड विकास अधिकारी धनंजय सिंह (PDS) सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने जीआईसी जनुवा-बिसवां आंगनबाड़ी केंद्र-बिसवां देहात द्वितीय ओपन जिम-बिसवां देहात प्राथमिक विद्यालय-मझिगवां कला ग्राम पंचायत शिवथाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मियावाकी प्लांटेशन एवं आरआर सेंटर तथा ग्राम पंचायत कमुआ में प्राकृतिक खेती का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत कमुआ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं कृषि सखियों ने केंद्रीय प्रभारी अधिकारी का स्वागत करते

हुए प्राकृतिक खेती के विभिन्न मॉडलों का प्रदर्शन किया। कृषि सखियों ने जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, प्राकृतिक कीट एवं रोग प्रबंधन सहित प्राकृतिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी तथा बताया कि किस प्रकार प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों की लागत में कमी तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने आजीविका आधारित उद्यमों, महिला सशक्तिकरण एवं सामुदायिक सहभागिता से जुड़े अनुभव भी साझा किए। उमेश कुमार सिंह ने एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं एवं कृषि सखियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन के रूप में विकसित करने, अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने तथा महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुँचाया जाए तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती तथा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीक्षा जोशी (IAS) ने जनपद सीतापुर में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं आकांक्षात्मक विकास खंड बिसवां की उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। वहीं खंड विकास अधिकारी नंजय सिंह (PDS) ने विकास खंड स्तर पर संचालित योजनाओं, नवाचारों एवं ग्रामीण विकास से जुड़े प्रमुख कार्यों से केंद्रीय प्रभारी अधिकारी को अवगत कराया।

एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ, शिवाजी पार्क समेत विभिन्न स्थानों पर हुआ वृक्षारोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 13 जुलाई प्रधानमंत्री के आह्वान पर चलाए जा रहे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रविवार को इंदिरानगर क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरानगर आवासीय महासमिति के महासचिव सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के पार्षदों एवं मोहल्ला सुधार समितियों के पदाधिकारियों ने अपनी माताओं की स्मृति एवं सम्मान में पार्कों और घरों में पौधे लगाए तथा उनकी सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया। इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड स्थित शिवाजी पार्क में क्षेत्रीय पार्षद कल्पना वर्मा के नेतृत्व में कॉलोनीवासियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। वहीं पिकनिक स्पॉट रोड पर वन विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंदिरानगर के अनेक सामाजिक संगठनों ने सहभागिता करते हुए पौधे लगाए। कार्यक्रम में पार्षद रामकुमार वर्मा, दिनेश शुक्ला, नितिन सिंह पटेल, कैलाश जैन, सुनील त्यागी, डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. अंजु वार्ष्णेय, सुभाष शर्मा, पी.के. जैन, राकेश सिंह, देवी शरण त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

ककौली में विकास सिर्फ बोर्ड तक

जलभराव व टूटी सड़क से ग्रामीण परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में कायतों के बावजूद नहीं हुआ समाधान, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रोज झेल रहे परेशानी; ग्रामीणों ने लगाए उपेक्षा और भ्रष्टाचार के आरोप लखनऊ जनपद की बीकेटी विधानसभा क्षेत्र (169) के अंतर्गत फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड स्थित ककौली गांव के स्थानीय निवासी वर्षों से जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला और स्थानीय सभासद रामू कनौजिया से शिकायत करने के बावजूद आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की मुख्य सड़क लंबे समय से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव इतना अधिक हो जाता है कि राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग इस रास्ते पर फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो चुके

हैं। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि पूर्व में एक बच्चे की इस जलभराव और सड़क की बदहाली के कारण जान भी चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शासन द्वारा सड़क निर्माण का बोर्ड तो लगा दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विकास कार्य स्वीकृत हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क आज भी अपनी बदहाल स्थिति में है और निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों ने इसे विकास कार्यों में पारदर्शिता पर बड़ा सवाल और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार संबंधित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सड़क निर्माण और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अनदेखी के कारण गांव के हजारों नागरिक रोजाना कठिनाइयों का सामना करने को मजबूर हैं। ककौली गांव के निवासियों ने शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सड़क निर्माण कार्य को तत्काल शुरू कराया जाए तथा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को वर्षों से चली आ रही इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि जब विकास कार्यों के बोर्ड लगाए जा चुके हैं, तो आखिर सड़क निर्माण कार्य धरातल पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? और कब तक ककौली गांव के लोग बदहाल सड़क और जलभराव की इस समस्या से जूझते रहेंगे?

सरोजनीनगर को मिली बैंकिंग विकास की नई सौगात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करते हुए विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने सोमवार को सेक्टर-4, वृंदावन योजना स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को देश की आर्थिक मजबूती का आधार बताते हुए कहा कि बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की बचत को निवेश में परिवर्तित कर बैंक उद्योग, व्यापार और स्वरोजगार को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अपने संबोधन में डॉ. राजेश्वर सिंह ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लगभग 90 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1935 में स्थापित यह बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद भी निरंतर प्रगति की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करता रहा है। उन्होंने बैंक की पारदर्शी कार्यप्रणाली, उत्कृष्ट सेवा और जनविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का मात्र 0.13 प्रतिशत एनपीए (ह्रक्र) देश में सबसे कम होना उसकी मजबूत ऋण नीति, प्रभावी निगरानी और उत्कृष्ट रिकवरी

व्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन और समस्त कर्मचारियों को बधाई दी। विधायक ने प्रवर्तन निदेशालय में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें बैंकिंग प्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बैंक देश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लगभग साढ़े छह लाख करोड़ रुपये के व्यवसाय को उसकी विश्वसनीयता और क्षमता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत गोविंद सिंह, दीवाकर पांडे, अजय कुमार मौर्य, ममता यादव एवं रिद्धि पाण्डेय को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। डॉ. राजेश्वर सिंह ने सभी लाभार्थियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि सरकार की योजनाएँ युवाओं को रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए सशक्त बना रही हैं।

संक्षिप्त खबरें

बहराइच में 42.93 करोड़ की 14 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण

लखनऊ। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मुख्यालय से वर्चुअल माध्यम से जनपद बहराइच में पूरी हुई 14 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। करीब 42.93 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से जिले में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। लोकार्पित परियोजनाओं में चौधरी चरण सिंह सरयू पंप नहर (द्वितीय एवं तृतीय चरण) नानपारा का आधुनिकीकरण प्रमुख है। वर्ष 1984-85 में निर्मित इस पंप नहर में पुराने विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों को बदलकर नए पंप सेट, पाइप लाइन, विद्युत उपकरण और स्काडा प्रणाली स्थापित की गई है। करीब 35.76 करोड़ रुपये की लागत से हुए इस कार्य के बाद पंप नहर की क्षमता फिर से 240 क्यूसेक हो गई है। इससे लगभग 28,976 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और 21,387 हेक्टेयर सिंचन क्षमता बहाल हुई है।

आर्सेनिक-फ्लोराइड प्रभावित गांवों में 100% नल से जल सुनिश्चित करें: स्वतंत्र देव सिंह

लखनऊ। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित सभी गांवों में शत-प्रतिशत पाइप्ड वॉटर सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभावित गांव में नल से जल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जलशक्ति मंत्री ने सोमवार को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में जल जीवन मिशन, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग और स्वच्छ गंगा मिशन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन की सभी परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं। समीक्षा के दौरान मंत्री ने लखनऊ मंडल में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की अधिकांश परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं।

एलडीए कॉलोनी पोस्टमास्टर पर लापरवाही का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सरकारी कार्यालय में ड्यूटी के समय लापरवाही और अभद्र व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह के साथ LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ स्थित डाकघर के पोस्टमास्टर संदीप मिश्रा ने अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। दिनांक 10.07.2026 समय लगभग 11:30 बजे बृज मोहन सिंह 12 स्पीडपोस्ट भेजने हेतु एलडीए कॉलोनी डाकघर पहुंचे थे। काउंटर कर्मी द्वारा नकद लेने से मना कर ऑनलाइन भुगतान कराया गया तथा अस्पष्ट रसीद उपलब्ध कराई गई। शिकायत करने पर पोस्टमास्टर संदीप मिश्रा ड्यूटी के समय अपने मोबाइल पर किसी पुलिस अधिकारी से सिफारिश कर रहे थे एवं कार्यालय में AC चल रहा था। इस संबंध में अवगत कराने पर पोस्टमास्टर ने अभद्रता करते हुए कहा 'आपके जैसे बहुत लोग आते हैं, अपनी आवाज तेज मत करो '। आगे उन्होंने 2 महिलाओं को बुलाकर

प्रार्थी के विरुद्ध भला-बुरा कहलवाया तथा 'यहाँ से भगाओ' कहा। साथ ही यह भी कहा 'मैं भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, हमारी आवाज तुमसे तेज है '। प्रार्थी द्वारा ड्यूटी के समय निजी कार्य करने पर टोकने पर उन्होंने कहा 'जो करना है कर लो '। उक्त समस्त घटना का वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है। शिकायत का विवरणः द्वारा दिनांक 13.07.2026 को जिलाधिकारी लखनऊ, पुलिस उपायुक्त पश्चिम, थाना प्रभारी कृष्णा नगर को रजिस्ट्री AD द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा गया है एवं दिनांक 12.07.2026 को पोस्टमास्टर जनरल UP सर्किल, चीफ पोस्टमास्टर लखनऊ GPO एवं सचिव, डाक विभाग भारत सरकार नई दिल्ली को भी रजिस्ट्री भेजी जा चुकी है। मांगः प्रार्थी ने मांग की है कि पोस्टमास्टर संदीप मिश्रा के विरुद्ध BNS 2023 की धारा 351(2), 352, 189(2) के अंतर्गत FIR दर्ज कर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए तथा प्रार्थी एवं उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। सिंह ने कहा कि 'सरकारी कर्मचारी जनता का सेवक होता है। ड्यूटी के समय इस प्रकार का आचरण निंदनीय है। यदि 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय की शरण ली जाएगी '।

पशुधन की नस्ल सुधार और टीकाकरण पर जोर, लखनऊ में कार्यशाला आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने, नस्ल सुधार और टीकाकरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में कृत्रिम गर्भाधान, गुणवत्तापूर्ण टीकाकरण और डिजिटल अभिलेखीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव, पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि पशुधन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण के आच्छादन में गुणात्मक सुधार लाना है, जिससे पशुओं की उत्पादकता बढ़े और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने प्रतिभागियों से विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही जानकारी का उपयोग पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अभिलेखीकरण, टीकाकरण की माइक्रो प्लानिंग और भारत पशुधन एप के प्रभावी उपयोग से योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता को बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यशाला में भारत पशुधन एप पर फीडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया। इनमें हापुड़, पीलीभीत, कौशाम्बी, हरदोई और शामली शामिल रहे। वहीं टीकाकरण लक्ष्य में बेहतर उपलब्धि हासिल करने वाले जिलों अलीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद, जौनपुर और पीलीभीत को भी सम्मानित किया गया। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने सेक्स्ड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान, सीमेन स्ट्रॉ की कोल्ड चेन व्यवस्था, पशुओं के प्रबंधन, गर्भ परीक्षण, प्रसव प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।

जनसुनवाई में मंत्री ए.के. शर्मा ने सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पेयजल, आवास, सफाई, बिजली बिल संशोधन, अतिक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। गोमतीनगर में पेयजल समस्या की शिकायत पर मंत्री ने नगर आयुक्त गौरव कुमार से बात कर जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए। लखनऊ निवासी विजय की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर मंत्री ने केजीएमयू में बेहतर उपचार की व्यवस्था कराने को कहा। वहीं इटावा निवासी अतुल कुमार के ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के अनुरोध पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनसेवा और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

अब नहीं सील होंगे कोचिंग संस्थानः एलडीए

एलडीए ने कार्रवाई पर नरमी दिखाई, नियम पूरे करने पर मिलेगी संचालन की मंजूरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में कोचिंग संस्थानों पर चल रही सीलिंग कार्रवाई के बीच बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब बिना उचित कारण किसी भी कोचिंग संस्थान को सील नहीं किया जाएगा। साथ ही पहले से सील किए गए संस्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के प्रदेश प्रवक्ता मनीष राघव एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी कमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एलडीए कार्यालय पहुंचकर कोचिंग संचालकों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। एलडीए उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में

अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने प्रतिनिधिमंडल से विस्तृत वार्ता की। बैठक के दौरान अपर सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि यदि किसी आवासीय क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पर्याप्त कारण किसी भी संस्थान को सील नहीं किया जाएगा और जो संस्थान पहले से सील किए गए हैं, उन्हें भी नियमानुसार खोला जा रहा है। एलडीए प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया कि मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों को पर्याप्त समय दिया जाएगा तथा कोचिंग संचालकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के प्रदेश प्रवक्ता मनीष राघव ने कहा कि संघ प्रदेश के सभी कोचिंग संचालकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी किसी भी संचालक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन निरंतर संघर्ष करता रहेगा।

कोचिंग संस्थानों को एलडीए की बड़ी राहत

- अब कोचिंग संस्थानों को सील नहीं किया जाएगा।
- नियमों का पालन करने वाले बंद संस्थानों को दोबारा खोलने की अनुमति मिलेगी।
- एलडीए ने कोचिंग संचालकों को कार्रवाई में राहत का आश्वासन दिया।
- सुरक्षा और भवन संबंधी मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।
- मानक पूरे करने वाले संस्थानों के संचालन का रास्ता होगा साफ।

बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज, मुख्य सचिव ने 44 जिलों की समीक्षा की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर प्रदेश के 44 संभावित बाढ़ प्रभावित जिलों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की गुणवत्ता बेहतर रखी जाए और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में घर-घर संपर्क अभियान चलाकर लोगों को बाढ़ से बचाव और आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक किया जाए। मुख्य सचिव ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के संसाधनों का स्थानीय नाविकों एवं प्रशिक्षित तैराकों के सहयोग से

बेहतर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी जर्जर भवनों को चिन्हित कर समयबद्ध मरम्मत कराने और बाढ़ प्रबंधन से जुड़े सभी जरूरी टेंडर जल्द पूरे करने को कहा। एस.पी. गोयल ने कहा कि राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने प्रभावित नागरिकों की गरिमा और सम्मान का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में मॉडल फ्लड शेल्टर विकसित करने पर भी जोर दिया, ताकि आपदा के समय लोगों को सुरक्षित और बेहतर आश्रय मिल सके।

ईरान पर अमेरिकी हमले, सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा

140 सैन्य ठिकाने बने निशाना, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका-ईरान आमने-सामने

अमेरिका ने रविवार को होर्मुज क्षेत्र में एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर कई चरणों में हवाई हमले किए। इनमें मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, गोला-बारूद के भंडार, संचार केंद्र और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान शामिल रहे। इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान में मिसाइल हमलों की चेतावनी के बीच सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया।

नई दिल्ली/वॉशिंगटन(एजेंसी)। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हालिया सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा होने की घोषणा की है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोमवार को बताया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों में वायु रक्षा प्रणाली, रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग ठिकानों तथा छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार लड़ाकू विमान, युद्धपोत, हवाई ड्रोन और नौसैनिक ड्रोन का संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया गया। सेंटकॉम ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण नहीं है और अमेरिकी सेना व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने रविवार को होर्मुज क्षेत्र में एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर कई चरणों में हवाई हमले किए। इनमें मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, गोला-बारूद के भंडार, संचार केंद्र और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान शामिल रहे। इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान में मिसाइल हमलों की चेतावनी के बीच सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। बहरीन में सोमवार तड़के सायरन भी बजे, हालांकि तत्काल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। ईरान के सरकारी मीडिया ने देश के कई हिस्सों में ताजा हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए कम से कम एक व्यक्ति की मौत की जानकारी दी। वहीं, ईरान ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जबकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि समुद्री मार्ग अब भी खुला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर 'जबरदस्त बमबारी' की है। दूसरी ओर, ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'एकतरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है।' इस बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि क्षेत्र में व्यापक युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।

कैलाश पर्वत आज भी अजेय, रहस्य और आस्था का अनोखा संगम

एवरेस्ट पर हजारों ने चढ़ाई की, लेकिन कैलाश की चोटी आज तक मानव के लिए अछूती

बताया जाता है कि वर्ष 2001 में चीन ने हेलीकॉप्टर से पर्वत के ऊपर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने के कारण उसे लौटना पड़ा। इसके बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मानसरोवर झील का मीठा जल और राक्षसताल का खारा पानी भी लोगों के लिए आकर्षण और शोध का विषय हैं। कई लोग कैलाश को 'एक्सिस मुंडी' (ब्रह्मांड का केंद्र) भी मानते हैं।

नई दिल्ली(एजेंसी)। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत आज भी मानव के कदमों से अछूता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माने जाने वाले इस पर्वत को लेकर आस्था और रहस्य दोनों जुड़े हुए हैं। शोधार्थी रजत रमन दीक्षित के अनुसार, कैलाश से अधिक ऊंचे 100 से ज्यादा पर्वतों पर चढ़ाई हो चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक किसी ने विजय हासिल नहीं की। वर्ष 1985 में प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को चीन सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसकी पवित्रता का सम्मान करते हुए इसे ठुकरा दिया। बताया जाता है कि वर्ष 2001 में चीन ने हेलीकॉप्टर से पर्वत के ऊपर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने के कारण उसे लौटना पड़ा। इसके बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मानसरोवर झील का मीठा जल और राक्षसताल का खारा पानी भी लोगों के लिए आकर्षण और शोध का विषय हैं। कई लोग कैलाश को 'एक्सिस मुंडी' (ब्रह्मांड का केंद्र) भी मानते हैं। हालांकि, कैलाश पर्वत से जुड़े कई दावे और भौगोलिक तथ्यों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद यह पर्वत आस्था, अध्यात्म और रहस्य का अद्भुत प्रतीक बना हुआ है।

मुंह के छालों से राहत देंगे ये आसान घरेलू उपाय

नई दिल्ली। मुंह के छाले भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके कारण खाने, पीने और बोलने में काफी दर्द और जलन होती है। अधिकांश मामलों में ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ घरेलू उपाय असहजता कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मुंह के छाले विटामिन बी-12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव, मुंह में चोट या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण हो सकते हैं। छालों में नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना सबसे सामान्य उपाय माना जाता है। नमक के एंटीमाइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया को कम करने और सूजन घटाने में सहायक हो सकते हैं। वहीं शहद के एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जलन कम करने और प्रभावित हिस्से पर सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करते हैं। नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड बैक्टीरिया और सूजन से लड़ने में सहायक माना जाता है तथा प्रभावित हिस्से में नमी बनाए रखकर दर्द कम कर सकता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा मुंह के पीएच स्तर को संतुलित कर जलन कम करने में मदद कर सकता है। दर्द से तत्काल राहत के लिए ठंडा पानी या बर्फ की सिकाई भी लाभदायक हो सकती है, हालांकि बर्फ को सीधे लंबे समय तक छाले पर नहीं रखना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मुंह के छाले दो सप्ताह से अधिक समय तक बने रहें, बार-बार हों या अत्यधिक दर्द व बुखार जैसी समस्या के साथ दिखाई दें, तो घरेलू उपचार पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सक से जांच और उचित उपचार कराना चाहिए।

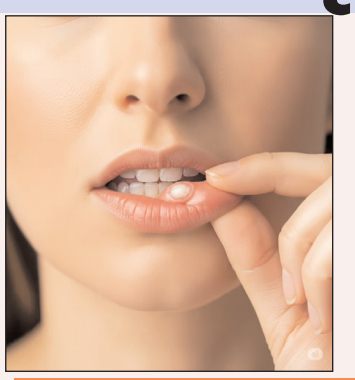

विशेषज्ञों के अनुसार, मुंह के छाले विटामिन बी-12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव, मुंह में चोट या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण हो सकते हैं। छालों में नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना सबसे सामान्य उपाय माना जाता है। नमक के एंटीमाइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया को कम करने और सूजन घटाने में सहायक हो सकते हैं। वहीं शहद के एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जलन कम करने और प्रभावित हिस्से पर सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करते हैं।

नियमित कॉफी से लिवर रोगों का खतरा घट सकता है: अध्ययन

रिसर्च में सिरोसिस और लिवर कैंसर का जोखिम कम मिलने के संकेत, विशेषज्ञ बोले- केवल कॉफी पर न रहें निर्भर

कॉफी पीने वालों के लिए एक नई रिसर्च राहत भरी खबर लेकर आई है। अमेरिका के सीडर्स-सिनाई के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से कॉफी पीने वाले लोगों में लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और लिवर संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम कम हो सकता है। यह अध्ययन मेडिकल जर्नल क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। शोध में ब्रिटेन के यूके बायोबैंक से जुड़े करीब 3.55 लाख लोगों के स्वास्थ्य आंकड़ों का लगभग 13 वर्षों तक विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार, रोजाना पांच या उससे अधिक कप कॉफी पीने वालों में सिरोसिस का खतरा 32 प्रतिशत, लिवर कैंसर का खतरा 47 प्रतिशत और लिवर संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम 42 प्रतिशत तक कम पाया गया। हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग अधिक मात्रा में कॉफी पीना शुरू कर दें। अध्ययन में एक से चार कप प्रतिदिन कॉफी पीने वालों में भी सकारात्मक संबंध देखने को मिला, जबकि तीन से चार कप पीने वालों में लाभ सबसे अधिक दिखाई दिया। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. जू डोंग यांग के अनुसार, जो लोग कॉफी आसानी से पचा लेते हैं, उनके लिए सामान्य मात्रा में इसका सेवन लाभकारी हो सकता है। लेकिन केवल लिवर की सुरक्षा के उद्देश्य से कॉफी पीना शुरू करने की सलाह नहीं दी जा सकती। शोध में यह भी पाया गया कि कॉफी पीने वालों के लिवर में फैट, सूजन और फाइब्रोसिस के संकेत अपेक्षाकृत कम थे। दिलचस्प बात यह रही कि कैफीनयुक्त और डिकैफ (बिना कैफीन) दोनों प्रकार की कॉफी से समान लाभ जुड़े पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि कॉफी में मौजूद अन्य जैविक तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए केवल कॉफी पर्याप्त नहीं है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मधुमेह पर नियंत्रण और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों से बचाव भी उतना ही आवश्यक है।

यह अध्ययन मेडिकल जर्नल क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। शोध में ब्रिटेन के यूके बायोबैंक से जुड़े करीब 3.55 लाख लोगों के स्वास्थ्य आंकड़ों का लगभग 13 वर्षों तक विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार, रोजाना पांच या उससे अधिक कप कॉफी पीने वालों में सिरोसिस का खतरा 32 प्रतिशत, लिवर कैंसर का खतरा 47 प्रतिशत और लिवर संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम 42 प्रतिशत तक कम पाया गया। हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग अधिक मात्रा में कॉफी पीना शुरू कर दें।

शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अध्ययन केवल कॉफी सेवन और बेहतर लिवर स्वास्थ्य के बीच संबंध दर्शाता है, इससे यह साबित नहीं होता कि कॉफी ही इन लाभों का प्रत्यक्ष कारण है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाटा प्रोजेक्ट्स का 940 करोड़ का हाईवे कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया, कहा- NHAI का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला 'पहले से तय'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI), जो संविधान के आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' (State) है, मनमाने ढंग से हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही खत्म नहीं कर सकती और न ही देरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकती है, जब देरी खुद अथॉरिटी की गलती से हुई हो—जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिना किसी रुकावट वाली ज़मीन और साफ़ रास्ता न सौंप पाना। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी ने कहा, 'इस मामले में आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली पार्टी का काम जनहित के काम को प्रभावित करने वाला और मनमाना पाया गया। इसलिए यह कोर्ट व्यापक जनहित में न्याय के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। अगर नेशनल हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट में देरी 'राज्य' (जो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी है) की लापरवाही, असावधानी और मनमानी के कारण होती है तो कोर्ट के लिए इस याचिका में उठाए गए ऐसे कदमों के असली कारणों को समझने के लिए 'कॉर्पोरेट आवरण' (corporate veil) को हटाकर देखना पूरी तरह सही है।' NHAI ने दिसंबर 2018 में गढ़मुक्तेश्वर और मेरठ के बीच NH-709 के 50.254 km हिस्से को चौड़ा और अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव मंगाए, जिसकी लागत ?940.68 करोड़ थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को चुना गया और मार्च 2021 में एक्सेप्टेंस लेटर (स्वीकृति पत्र) जारी किया गया। काम शुरू करने की तारीख 10 अक्टूबर 2021 तय की गई थी और काम पूरा करने की समय-सीमा 10 अक्टूबर 2023 थी। 21 सितंबर 2021 के हैंडओवर मेमोरेंडम में कुल लंबाई के 47.620 द्मद्व, यानी 94.76% हिस्से के सौंपे जाने की बात दर्ज थी। याचिका को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने 14 जनवरी 2025 के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश उसके बाद बैंक गारंटी ज़ब्त करने की कार्रवाई और 3 फरवरी 2025 को जारी नए टेंडर रद्द किया। कॉन्ट्रैक्टर के 14 महीनों में काम पूरा करने के वादे को रिकॉर्ड करते हुए और यह देखते हुए कि किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बने थे और कब्ज़ा कॉन्ट्रैक्टर के पास ही था, कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे एक महीने के भीतर साइट का नया संयुक्त निरीक्षण करें और EPC एग्रीमेंट के तहत बड़े जनहित में प्रोजेक्ट का नया शेड्यूल बनाकर उसे पूरा करें।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी ने कहा, 'इस मामले में आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली पार्टी का काम जनहित के काम को प्रभावित करने वाला और मनमाना पाया गया। इसलिए यह कोर्ट व्यापक जनहित में न्याय के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी।

पति-पत्नी की तरह साथ रहने पर वैध विवाह का कड़ा सबूत मांगकर भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हों और उनका वैवाहिक संबंध अन्य परिस्थितियों से स्थापित होता हो, तो भरण-पोषण के दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वैध विवाह का सख्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जस्टिस अचल सचदेव ने यह टिप्पणी महाराजगंज फैमिली कोर्ट के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द करते हुए की, जिसमें महिला की भरण-पोषण याचिका केवल इसलिए खारिज कर दी गई थी क्योंकि वह स्वयं को विधिक रूप से विवाहित पत्नी साबित करने वाले दस्तावेज पेश नहीं कर सकी थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्ष 2017 में दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन किया था। इसके बाद वह पति के साथ रहने लगी और उनके संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ। महिला का आरोप था कि विवाह के बाद उससे अतिरिक्त दहेज, विशेषकर चार पहिया वाहन की मांग की गई, उसके साथ मारपीट की गई और अंततः उसे उसके नाबालिग बेटे के साथ घर से निकाल दिया गया। उसने अपने लिए 25,000 प्रति माह तथा बेटे के लिए 15,000 प्रति माह भरण-पोषण की मांग की थी। दूसरी ओर, पुरुष ने यह स्वीकार किया कि दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन किया था, वह महिला के साथ अपने सरकारी आवास में रहा और उनके संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ। हालांकि, उसने दहेज मांगने और प्रताड़ना के आरोपों से इनकार किया। हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पुरुष की इन स्वीकारोक्तियों की अनदेखी करते हुए केवल तकनीकी आधार पर महिला की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब दोनों के पति-पत्नी की तरह साथ रहने और उनके संबंध से संतान होने के तथ्य स्वीकार हैं, तब केवल वैध विवाह के कठोर प्रमाण के अभाव में भरण-पोषण से इनकार करना उचित नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चे को ?5,000 प्रतिमाह भरण-पोषण देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि धारा 125 द्बह्लक्क्त के तहत पिता का दायित्व वैध और अवैध, दोनों प्रकार की संतान का भरण-पोषण करना है।

मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम आईएएस अधिकारी धोखाधड़ी जाल साजी का है मुकदमा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे 2004 बैच के आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ मामला 2013 से 2015 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण विभाग के शीर्ष अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं से संबंधित है । फरवरी 2019 में, पंत उन 14 अधिकारियों में शामिल थे, जो पश्चिमी विद्युत वितरण निगम (डब्ल्यूईडीसी) से संबंधित थे और जिनके खिलाफ मेरठ के परिक्षितगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एक श्रम ठेकेदार की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसने विभाग के अधिकारियों पर अपने भुगतान रोकने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। हालांकि पंत का नाम एफआईआर में डब्ल्यूईडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में दर्ज है - यह पद उन्होंने 7 फरवरी, 2013 से 3 दिसंबर, 2015 तक संभाला था - लेकिन मुख्य आरोप सीधे तौर पर उन्हें लक्षित नहीं करते प्रतीत होते हैं। पंत वर्तमान में लखनऊ के संभागीय आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। जब 2019 में श्रम ठेकेदार शिवकुमार शर्मा की शिकायत पर यह मामला मूल रूप से दर्ज किया गया था, तब वे कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। एसआईटी प्रमुख और लंबित धोखाधड़ी मामले के बीच संबंध की खबर सबसे पहले हिंदी भाषा के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया चैनल ' टॉप सीक्रेट' पर दी थी । 'जो व्यक्ति स्वयं धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में जांच के दायरे में है, वही राम मंदिर में हुए गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की जांच कर रहा है! तो राम मंदिर की जांच निष्पक्ष कैसे होगी? यह ठीक वैसे ही होगी जैसे सरकार निर्देश देगी,' उपाध्याय ने 8 जुलाई को ङ्ग पर लिखा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राम मंदिर चंदा घोटाले के बारे में बात करते हुए इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने पंत का नाम लेते हुए कहा, 'भाजपा सरकार ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जिस पर लूट और गबन का आरोप है।' 'एसआईटी एक लीपापोती है। और मैंने सुना है कि एसआईटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसके एक सदस्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर दर्ज है। अब बताइए, क्या ऐसा व्यक्ति एसआईटी में बना रहेगा?' समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदली 8वीं की किताब ज्यूडिशियरी, नेताजी और बंटवारे वाले चैप्टर में बड़े बदलाव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कक्षा 8 की सोशल साइंस की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई पुस्तक में सिर्फ न्यायपालिका (ज्यूडिशियरी) वाले अध्याय में ही नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के बंटवारे और विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े हिस्सों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद किया गया, जिसमें पुराने संस्करण को वापस लेने और उसकी जगह नया संस्करण प्रकाशित करने को कहा गया था। संशोधित पुस्तक 'समाज का अध्ययनः भारत और उसके आगे' में आजाद हिंद फौज के गठन से जुड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भों में बदलाव किया गया है। पहले किताब में लिखा था कि नेताजी ने 'हिटलर' से मदद मांगी थी और हिटलर को उसकी 'नस्लवादी नाजी विचारधारा और विस्तारवादी लक्ष्यों' के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से जोड़ा गया था। नए संस्करण में हिटलर और नाजी विचारधारा से जुड़े ये सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। अब केवल यह कहा गया है कि नेताजी ने सेना खड़ी करने के लिए ब्रिटिश विरोधी ताकतों से समर्थन मांगा था। इतिहास के अध्याय India's Long Road to Independence में भारत के बंटवारे को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब किताब में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का व्यापक विरोध किया था और इसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता था या नहीं, यह आज भी बहस का विषय है। वहीं, पुरानी किताब में मौजूद वह पंक्ति हटा दी गई है, जिसमें कहा गया था कि विभाजन के दौरान जब उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक कत्लेआम हो रहा था, तब कांग्रेस नेता बेबस थे। इसके अलावा संशोधित पुस्तक में यह भी जोड़ा गया है कि 1925 में विनायक दामोदर सावरकर ने भी स्वराज की मांग की थी, जबकि पिछले संस्करण में इसका उल्लेख नहीं था। विवाद के बाद ज्यूडिशियरी वाले अध्याय को पूरी तरह दोबारा लिखा गया है। अब इसमें न्यायपालिका की आलोचना से हटकर उसकी संवैधानिक भूमिका और कार्यों को समझाने पर जोर दिया गया है। पहले जहां न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, न्यायिक देरी और न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों जैसे मुद्दों का जिक्र था, उन्हें हटाकर अब भारतीय न्यायपालिका की संरचना, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपाय, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL), ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही ई-फाइलिंग, हाइब्रिड कोर्ट हियरिंग और अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग जैसी हालिया तकनीकी पहलों की जानकारी भी दी गई है। संशोधित किताब के एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में कहा गया है कि यह संस्करण एक समीक्षा प्रक्रिया के बाद प्रकाशित किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) रिट याचिका में की गई थी। इसमें यह भी बताया गया है कि ज्यूडिशियरी वाले अध्याय को शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप दोबारा तैयार किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कंटेंट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ज्यूडिशियरी अध्याय के कुछ हिस्सों को आपत्तिजनक बताया था। अदालत ने NCERT को किताब की सभी प्रिंट और डिजिटल प्रतियां वापस लेने, उनके प्रसार पर रोक लगाने और संशोधित संस्करण प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।